15वें सार्क शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री का वक्तव्य

(दिनांक 2 अगस्त, 2008)

सर्वप्रथम मैं महामहिम राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को "दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन' का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देते हुये अपने भाषण की शुरुआत करता हूं। मैं 15वें शिखर सम्मेलन के उत्कृष्ट प्रबंधों के लिये तथा हम सभी के लिये गर्मजोशी तथा उदारतापूर्ण आतिथ्य के लिये श्रीलंका की सरकार तथा जनता की अत्यंत सराहना करता हूं।

हमारे सबसे नये प्रेक्षक मारीशस की भी, जिसके साथ दक्षिण एशिया के सुदीर्घ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, मैं बहुत हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन : सार्क की स्थापना के 23वर्षों के दौरान दक्षिण एशिया ने एक लम्बी दूरी तय की है। लोकतंत्र और राजनीतिक परिवर्तन की हवाऐं हमारे क्षेत्र से होकर गुजरी हैं। बेहतर जीवन और अपेक्षाकृत अधिक सशक्तिकरण के लिये हमारे लोगों की, विशेषकर हमारे युवाओं की आकाक्षाएं बहुत तेजी से लगातार बढ़ती जा रही हैं। भूमंडलीकरण के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्थायें अपने पड़ोसी देशों के साथ, कुल मिलाकर, विश्व के साथ एक दूसरे से अपेक्षाकृत अनेक अंतर्संबंधों से जुड़ी हैं।

लेकिन यह एक तथ्य है कि दक्षिण एशिया उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा है जितनी हम सभी की आकांक्षाएं रही हैं। हमें केवल आसियान के अंदर तेजी से हुए एकीकरण और एशिया में एक प्रमुख आर्थिक "ब्लाक' के रूप में इसके उदय को देखना है ताकि हम अपने सामने उपलब्ध अवसरों को समझ सकें।

हममें से प्रत्येक की सफलता और समृद्धि अन्य के लिये ऐसे अवसर उपलब्ध कराती हैं जिससे वे अपनी सफलता तथा समृद्धि को और आगे बढ़ायें। हितों की यह आपसी भावना हर स्थान पर क्षेत्रीय सहयोग की प्रमुख सहयोगी शक्ति है।

हमारा लक्ष्य अपने क्षेत्र में वृद्धि के गुणात्मक चक्रों को तैयार करना होना चाहिये। एक समृद्ध दक्षिण एशिया ही शान्तिपूर्ण और स्थिर दक्षिण एशिया भी बनेगा। इस आकांक्षा को पूरा करने के लिये हमारे दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाने और सृजनात्मक चिन्तन के एक नये सिद्धांत की आवश्यकता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन के मुख्य विषय "साझेदारी के माध्यम से प्रगति" को सार्थकता प्रदान करने के लिये हम कुछ कर सकते हैं तथा हमें और अधिक करना चाहिये।

हमारे क्षेत्र में आतंकवाद लगातार अपना सिर उठा रहा है। हमारी स्थिरता तथा हमारी प्रगति के लिये यह एकमात्र सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। हमें घृणा, कट्टरवादिता तथा हमारे सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने पर आमादा ताकतों के खिलाफ संघर्षों में हार नहीं माननी चाहिए।

आतंकवादी और उग्रवादी कोई सीमा नहीं मानते। काबुल में भारतीय दूतावास पर हाल का हमला तथा पिछले कुछ दिनों में हुये बंगलौर और अहमदाबाद में सिलसिलेवार विस्फोट बर्बरता की

भयंकर तबाही की याद दिलाते है जो दक्षिण एशिया में अभी चलाई जा रही हैं। हमें इस नासूर का मुकावला करने के लिये मिलजुल कर और दृढ़ता के साथ कार्रवाई करनी चाहिये। हमें बहुलतावाद, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और कानून के शासन के मूल्यों की रक्षा अवश्य करनी चाहिये।

दक्षिण एशिया में हमारे विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिये आवश्यक साधन और कौशल पूरी तरह मौजूद हैं। मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि पिछले चार वर्षों के दौरान भारत ने औसतन 8.8 प्रतिशत वार्षिक की दर से जोरदार वृद्धि की है। भारत अब एक खुली अर्थव्यवस्था है जिसमें हर जगह से निवेश का स्वागत है। हमारे क्षेत्र में अन्य देशों ने भी बेहतर ही किया है। इस समय एशिया विश्व अर्थव्यवस्था की प्रगति में अग्रणी बन गया है और दक्षिण एशिया इस पुनरूत्थान का एक अंग है।

हमारे क्षेत्र में यह वृद्धि निश्चितरूप से, बहुगुणित करनेवाला प्रभाव डाल रही है। विकास में हमारा अत्यधिक और विविध प्रकार का अनुभव है जिन्हें एक साथ जुटाकर हमे टिकाऊ क्षेत्रीय विकास और एकजुटता का एक प्रतिमान तैयार करने की दिशा में मिलकर सहयोग करना चाहिये। "सार्क विकास कोष' ने मातृ एवम् शिशु संरक्षण की दो परियोजनायें प्रारम्भ करके शानदार शुरुआत की है। पिछले वर्ष इस क्षेत्र के हर देश में सार्क मॉडल ग्रामों का विकास किया जाना अत्यन्त उत्साहवर्धक कार्य है। हमें इन अभिनव कार्यक्रमों का प्रचलन जारी रखना चाहिये।

आगामी वर्षों के दौरान आर्थिक सहयोग, आपसी सम्पर्क और एकीकरण सार्क के लिये आधारस्तम्भ होंगे। हम "दक्षिण एशियाई कस्टम्स यूनियन' और दक्षिण एशियाई आर्थिक यूनियन का निर्माण कार्य योजनाबद्ध तथा क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिये पहले ही सहमत हो चुके हैं।

भारत ने लक्ष्य से एक वर्ष पहले अर्थात 1 जनवरी 2008 से ही एल.डी.सी. सदस्यों के वास्ते अपने बाजारों के लिये "शून्य शुल्क प्रवेश' स्वीकार कर लिया है और इन देशों के लिये हमारी संवेदन सूची को भी सीमित कर रखा है। श्रीलंका के साथ भारत का एफ.टी.ए. संतोषजनक ढंग से चल रहा है और दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था के लिये उसका लाभ पहुंच रहा है।

इस प्रकार की प्रारम्भिक पहलों के साथ हम सभी जितनी सुविधाजनक रफ्ततार से चल सकेंगे, आगे बढ़ते जायेंगे।

सभी नेताओं ने भौतिक सम्पर्क के महत्व पर जोर दिया है। भारत ने अपनी ओर से रक्सौल-बीरगंज और जोगबनी-विराटनगर सीमाओं पर बड़ी लाइन के अपने सम्पर्क का स्तर बढ़ा दिया है, ढाका-कोलकाता रेल सेवा शुरु हो गई है और अन्य पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमाओं के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिये भी कार्य चल रहा है। भारत मोटरवाहनों तथा रेल संबंधी प्रारूप समझौतों को अंतिम रूप देने के लिये आगे बढ़ने को उत्सुक है।

मेरा हमेशा से यह यकीन रहा है कि दक्षिण एशिया के लोग अपने से भी ज्यादा पश्चिम के देशों के बारे में जानते हैं। हमारे छात्रों और विदेशों में गये पेशेवर लोगों के बीच जो बंधुत्व की भावना

मौजूद है, उसे इधर दक्षिण एशिया में भी फिर से पैदा करना चाहिये। प्रथम सार्क सांकृतिक समारोह तथा प्रथम सार्क युवा शिविर के आयोजन के फलस्वरूप जो शानदार प्रतिक्रिया पैदा हुई है, उससे ऐसे आदान-प्रदानों के लिये अंतर्निहित अभिलाषा परिलक्षित होती है ।

हम दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर बहुत उत्साहित हैं। नई दिल्ली में इस विश्वविद्यालय के लिये भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और एक परियोजना कार्यालय भी स्थापित कर लिया गया है। 2010 में जब इस विश्वविद्यालय का कार्यसंचालन शुरू हो जायेगा तो इसमें 5000 छात्रों को अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त होगा और यहां विश्व स्तर के वैज्ञानिकों, प्रोद्यौगिकीविदों और विचारकों का एक पूल तैयार हो जायेगा। वे जब दुनिया में जायेंगे तो वे सिर्फ अपने अपने देशों का ही नहीं अपितु समूचे दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करेंगे।

भविष्य में उभरनेवाली नई नई चुनौतियों की पहचान और उनका समाधान करने के लिये इसे एक गतिशील और अनुक्रियात्मक संस्था का रुप लेना होगा। तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण हमारे विकास के लाभों की रफ्तार में अवरोध का खतरा बढ़ जायेगा।

सार्क को यह सुनिश्चित करने के लिये कि वह एक ऐसी प्रभावी वैश्विक अनुक्रिया दे सके जो तेल की खपत करने वाले देशों के हितों की रक्षा करता है, यह सुनिश्चित करने के लिये विश्व की परिषदों में उसे अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। हमें सौर ऊर्जा, जलविद्युत और वायु ऊर्जा, जो दक्षिण एशिया में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसे बार बार इस्तेमाल हो सकने वाले हमारे संसाधनों का पूल भी तैयार करना होगा।

2007 में सार्क फूड बैंक की स्थापना अग्रिम विचार वाले निर्णय का एक अच्छा उदाहरण था। आज के भूमंडलीय खाद्य संकट के संदर्भ में, यह निर्णय हमारी दूरदर्शिता और अपनी सहायता स्वयं करने की हमारी योग्यता का एक उदाहरण है। हमें अब सभी सदस्य देशों को अंतर-शासकीय समझौते के शीघ्र पुष्टीकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

हम भारतवासी बड़ी व्यग्रता से दूसरी हरित क्रान्ति की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। दक्षिण एशिया देशों को सामूहिक जिम्मेदारी से काम करने की जरुरत है जिससे कृषि उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादन और कृषि के आमदनी में बड़ी तेजी से वृद्धि हो ताकि हमारे क्षेत्र से खाद्य पदार्थों की कमी तथा भुखमरी की समस्या की लटकती तलवार न दिखाई पड़े ।

भारत सदस्य देशों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से कार्य करेगा जिससे उन कई प्रस्तावों को कार्य रूप दिया जा सके जिनमें पशुओं के प्रजनन संबंधी ज्ञान और अनुभवों का बेहतर आदान-प्रदान करना, प्रोटीन से भरपूर दालों के उत्पादन में सुधार और फसलों की कटाई के बाद की आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के मामले में सुधार आ सके।

हम विश्व में सबसे अधिक संवेदनशील प्रणालियों में से एक प्रणाली के उत्तराधिकारी और न्यासी हैं। यह सबसे उत्साहजनक है कि हमारे मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन संबंधी सार्क की

कार्ययोजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है जिसमे ऐसे तीव्र विकास को मान्यता दी गयी है जो अपनाये जाने के सर्वोत्तम रूप में उपलब्ध है।

हाल ही में भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्ययोजना शुरू की है और हम उसके अनुभवों की भागीदारी के मामले में अत्यधिक इच्छुक हैं । इस योजना में कई ऐसे क्षेत्र है जिनमें सार्क सदस्य देशों के साथ हमें सहयोग करने की आवश्यकता है जैसे हिमालयीय पर्यावरण प्रणाली को स्थायित्व प्रदान करने संबंधी हमारा मिशन, समुद्र तटवर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के लिये हमारी योजनायें , आपदा प्रबंधन की नीतियां तथा कार्यक्रमों में पर्यावरण के मॉडल तैयार करने के संबंध में समयपूर्व चेतावनी प्रणालियों और संबद्ध अनुसंधान कार्य आदि शामिल है। जल प्रबंधन तथा वनरोपण के बारे में सार्क की परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं लेकिन हमें इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

मुझे विश्वास है कि हम श्रीलंका के सक्षम नेतृत्व के तहत इन प्रयासें को और आगे ले जाते रहेंगे। हाल के वर्षों में हमने कार्रवाई और कार्यान्वयन पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है और मुझे यह जान कर खुशी है कि इनके परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं। हम ज्यों-ज्यों अपनी प्राथमिकताओं को सुदृढ़ रूप देंगे और अपने कार्यकलापों को तर्कसंगत बनाएंगे, त्यों-त्यों सार्क के लाभों को अपने लोगों के दरवाजे के और निकट लाने में सक्षम हो जायेंगे।

भारत एक स्थिर, गतिशील और समृद्ध दक्षिण एशिया के विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिये तैयार है। मैं अपने सामूहिक भविष्य के बारे में आशावान हूं और मुझे विश्वास है कि हमें सर्वोत्तम लाभ अवश्य मिलेगा।

***